बहुजन हिताय! सक्षम भारत बहुजन सुखाय!

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 245 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 17 जुलाई 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागारिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

25 हजार के मुचलके और सख्त शर्तों के साथ खुर्शीद अली रिहा, फर्जी वीजा-पासपोर्ट मामले में मिली राहत

नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने महिपालपुर स्थित होटल से फर्जी वीजा और पासपोर्ट रैकेट के मामले में गिरफ्तार आरोपी खुर्शीद अली को नियमित जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि आरोपित के खिलाफ आगे कोई बरामदगी नहीं होनी है, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है और केवल जांच लंबित होने के आधार पर उसे अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रखा जा सकता। अदालत ने दो स्थानीय जमानतदारों और 25-25 हजार रुपये के निजी व जमानती बांड पर आरोपित को जमानत देने का आदेश दिया।

'परिसीमन बिल' पर आर-पार के मूड में कांग्रेस, जयराम रमेश ने किया कड़े विरोध का ऐलान किया

नई दिल्ली । कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गुरुवार को कहा कि अगर संसद के आगामी मॉनसून सत्र में प्रस्तावित परिसीमन बिल को दोबारा पेश किया जाता है, तो पार्टी उसका कड़ा विरोध करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार एक ऐसे उपाय के लिए समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रही है, जिसे पहले लोकसभा में जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल पाया था। कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रमेश ने कहा कि पार्टी ने उन बिलों पर विस्तार से चर्चा की है जिन्हें सत्र के दौरान पेश किए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पार्टी को अभी तक सरकार का आधिकारिक विधायी एजेंडा नहीं मिला है और 19 जुलाई को होने वाली सर्वदलीय बैठक में उन्हें इसकी जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा, 'हमने सुना है कि गृह मंत्री परिसीमन बिल को दोबारा पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। 17 अप्रैल को सरकार को इस बिल के लिए दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल पाया था, जो एक बड़ी हार थी। वे उस बिल को वापस लाना चाहते हैं।' पार्टी का रुख दोहराते हुए रमेश ने कहा, 'कांग्रेस पार्टी का रुख हमेशा से स्पष्ट रहा है: हम परिसीमन बिल का कड़ा विरोध करेंगे और आगे भी ऐसा करते रहेंगे। हम सभी विपक्षी दलों के बीच एकता बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे।' उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विपक्षी दलों में फूट डालकर कानून पारित करने के लिए जरूरी संख्या जुटाने की कोशिश कर रही है। 'यह सच है कि 17 अप्रैल के बाद से गृह मंत्री ने एक-दो विपक्षी पार्टियों में फूट डलवाई है। यह संविधान का अपमान है। वे चालाकी से दो-तिहाई बहुमत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी चालाक चालों और दूसरी पार्टियों को तोड़कर दो-तिहाई बहुमत हासिल करना संविधान का अपमान है; यह एक दागदार बहुमत होगा। हालांकि, लोकसभा में उनके दो-तिहाई बहुमत हासिल करने की कोई संभावना नहीं है,' उन्होंने कहा। 'हम विपक्षी पार्टियों के संपर्क में हैं; राहुल गांधी संपर्क में हैं, और हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उन सभी पार्टियों के संपर्क में हैं जिन्होंने 16 और 17 अप्रैल को परिसीमन बिल का पुरजोर विरोध किया था,' उन्होंने आगे कहा।

महिला आरक्षण अधिनियम का जिक्र करते हुए, रमेश ने कहा कि कांग्रेस महिलाओं के लिए आरक्षण का समर्थन करती है, लेकिन इसे प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ने का विरोध करती है। 'हमने पहले ही, 16 और 17 अप्रैल को, मौजूदा लोकसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों के आरक्षण के बारे में अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 में महिलाओं के लिए इस एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान शामिल है... अगर आप 543 सदस्यों वाली लोकसभा का एक-तिहाई हिस्सा निकालें, तो यह 181 होता है। इसलिए, महिला आरक्षण का प्रावधान लाएं, और हम पूरा समर्थन देंगे। हालांकि, महिला आरक्षण अधिनियम के नाम से पेश किया गया परिसीमन बिल असल में महिला आरक्षण की आड़ में लाया गया एक खतरनाक परिसीमन बिल था,' उन्होंने कहा। रमेश ने यह भी कहा कि कांग्रेस सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले कई अन्य बिलों का भी विरोध करेगी, जिनमें बर्खास्तगी से संबंधित प्रस्तावित संविधान संशोधन बिल, 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, 2025', विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम में संशोधन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम , 2013 में प्रस्तावित संशोधन शामिल है। 'हम 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल' का भी विरोध करेंगे... FCRA बिल के आने की भी संभावना है; हम उसका भी विरोध करेंगे... हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में संशोधनों के पक्ष में नहीं हैं और उनका पुरजोर विरोध करेंगे,' उन्होंने कहा। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी ने 'एक देश, एक चुनाव' पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पर भी चर्चा की, जिसके 10 अगस्त तक आने की उम्मीद है। 19 जुलाई को होने वाली सर्वदलीय बैठक से पहले, रमेश ने केंद्र सरकार पर इन बैठकों के कामकाज को लेकर निशाना भी साधा। उन्होंने इन्हें 'औपचारिकता' बताया और दावा किया कि विपक्षी दलों के सुझावों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसी बैठकों में भले ही 35 से 40 नेता शामिल होते हों, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और एक राज्य मंत्री सिर्फ 'सुनते हैं और नोट्स लेते हैं,' जबकि फ़ैसले आखिरकार 'वे दो लोग लेते हैं जिनके हाथ में असली ताक़त होती है।' सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक डेढ़ घंटे तक चली। इसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और संसदीय रणनीति समूह के सभी सदस्य मौजूद थे। संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 17 अप्रैल को लोकसभा में पास नहीं हो पाया था; इसे पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट मिले थे, जो संविधान के तहत जरूरी दो-तिहाई बहुमत से कम थे। हालांकि ऐसी अटकलें हैं कि केंद्र सरकार 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलने वाले मॉनसून सत्र के दौरान इसका संशोधित रूप फिर से पेश कर सकती है, लेकिन सरकार ने अभी तक अपने विधायी एजेंडे की आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

सीबीआई की याचिका पर बढ़ीं मुश्किलें, हाई कोर्ट ने केजरीवाल-सिसोदिया को दिया आखिरी मौका'

नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप नेता दुर्गेश पाठक को एक आखिरी मौका दिया। यह मौका उन्हें सीबीआई की उस रिवीजन याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए दिया गया है, जिसमें दिल्ली आबकारी नीति मामले में सभी आरोपियों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। जस्टिस मनोज जैन ने गौर किया कि सुनवाई के दौरान केजरीवाल, सिसोदिया और पाठक समेत किसी भी प्रतिवादी की ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ। कोर्ट को बताया गया कि पहले मौका दिए जाने के बावजूद, सिर्फ़ इन तीन प्रतिवादियों ने ही अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। देरी पर ध्यान देते हुए, बेंच ने उन्हें अपना जवाब रिकॉर्ड पर लाने का एक आखिरी मौका दिया और साफ़ कर दिया कि कार्यवाही में और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब इस मामले की सुनवाई के लिए 17 और 18 अगस्त की तारीख तय की गई है। सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल छत्र सिंह ने कोर्ट से सुनवाई जल्दी करने और मामले को जुलाई के आखिरी हफ्ते में लिस्ट करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इस मामले पर जल्द विचार करने की ज़रूरत है। बेंच ने कहा कि वह देखेगी कि क्या तारीखें पहले की जा सकती हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि ऐसा करना 'थोड़ा मुश्किल' लग रहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर उसका बोर्ड इजाज़त देगा तो वह इस संभावना पर फिर से विचार करेगी। हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मामले में लागू अंतरिम आदेश सुनवाई की अगली तारीख तक जारी रहेगा। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और दुर्गेश पाठक समेत सभी आरोपियों को बरी करने वाले ट्रायल कोर्ट के 27 फरवरी के फैसले को चुनौती दी है।

इससे पहले, जब मामला जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से जस्टिस मनोज जैन को ट्रांसफर किया गया था, तो हाई कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि वह केजरीवाल, सिसोदिया और पाठक को मामले के ट्रांसफर के बारे में औपचारिक रूप से सूचित करे। कोर्ट ने कहा था कि भले ही ट्रांसफर की खबर मीडिया में बड़े पैमाने पर आई हो, फिर भी औपचारिक सूचना दी जानी चाहिए ताकि सभी पक्ष मौजूदा बेंच के सामने पेश हो सकें।

दिल्ली में गरीब परिवारों को बड़ी सौगातः अब मिलेंगे बड़े घर, सरकार ने ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के कमरों का बढ़ाया आकार

नई दिल्ली ।दिल्ली सरकार ने झुग्गी बस्तियों में रहने वाले गरीब परिवारों को बेहतर और सम्मानजनक आवास देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। भलस्वा स्थित 7400 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के कमरों का आकार बढ़ा दिया गया है, जिससे लाभार्थियों को पहले की तुलना में अधिक बड़े और सुविधाजनक घर मिलेंगे। पुराने फ्लैटों के डिजाइन में बदलाव कर उनका कारपेट एरिया चार से पांच वर्गमीटर तक बढ़ाया गया है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने बृहस्पतिवार को परियोजना का निरीक्षण करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अंतिम दौरे के बाद पात्र झुग्गी परिवारों को इन फ्लैटों का चरणबद्ध आवंटन शुरू किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने भलस्वा स्थित ईडब्ल्यूएस आवास परियोजना का निरीक्षण कर निर्माण और मरम्मत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों के साथ फ्लैटों के कमरों, फर्श और नए निर्माण कार्य का जायजा लिया। मंत्री ने बताया कि पहले से बने फ्लैटों का स्वरूप बदलकर उन्हें आधुनिक जरूरतों के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। प्रत्येक फ्लैट का कारपेट एरिया कम से कम चार से पांच वर्गमीटर तक बढ़ाया गया है, ताकि परिवारों को रहने के लिए पहले से अधिक जगह मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल मकान देना नहीं, बल्कि ऐसा घर देना है जिसमें गरीब परिवार सम्मान और सुविधा के साथ रह सकें। दिल्ली की अनेक झुग्गी बस्तियों में रहने वाले हजारों परिवार लंबे समय से स्थायी आवास मिलने का इंतजार कर रहे हैं। भलस्वा में तैयार 7400 ईडब्ल्यूएस फ्लैट भी काफी समय से आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने की राह देख रहे हैं। अब सरकार का कहना है कि परियोजना अंतिम चरण में है और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होते ही आसपास की झुग्गियों में रहने वाले पात्र परिवारों को चरणबद्ध तरीके से इन फ्लैटों का आवंटन शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में वर्षों से अपने नाम पक्के घर की उम्मीद लगाए बैठे लोगों के लिए यह परियोजना नई उम्मीद लेकर आई है। मंत्री ने बताया कि जल्द ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता परियोजना का संयुक्त निरीक्षण करेंगी। उनके सुझावों के बाद केंद्रीय गृह मंत्री और संबंधित अधिकारियों से अंतिम सहमति ली जाएगी। इसके बाद आवंटन प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी ताकि पात्र परिवारों को बिना किसी परेशानी के मकान मिल सके। आशीष सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में पुराने बने फ्लैटों को प्रधानमंत्री आवास योजना के मानकों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। पहले से तैयार ढांचे का बेहतर उपयोग करते हुए कमरों का विस्तार किया गया है। इससे सरकारी धन का बेहतर उपयोग भी होगा और लाभार्थियों को पहले की तुलना में अधिक बेहतर आवास मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री की गारंटी को जमीन पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है।

दिल्ली में झुग्गीवासियों के पुनर्वास का मुद्दा लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। सरकार इस परियोजना को जहां झुग्गी, वहां मकान के संकल्प की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रही है। मंत्री ने कहा कि अब लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा कर लोगों तक उनका लाभ पहुंचाया जाएगा। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर परियोजना को वर्षों तक लंबित रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब जिम्मेदारी टालने का दौर समाप्त हो चुका है और सरकार परिणाम देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। भलस्वा की यह परियोजना केवल 7400 फ्लैटों का निर्माण नहीं, बल्कि हजारों गरीब परिवारों की जिंदगी बदलने की उम्मीद से जुड़ी है।

हौज खास में निकली भगवान जगन्नाथ की सबसे बड़ी रथयात्रा, एलजी बोले- सेवा ही सर्वोच्च मूल्य

नई दिल्ली । उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने बृहस्पतिवार को हौज खास में भगवान जगन्नाथ मंदिर में आयोजित 48वीं वार्षिक रथयात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रथयात्रा केवल धार्मिक आस्था का उत्सव नहीं, बल्कि सेवा, विनम्रता और समानता जैसे भारतीय जीवन मूल्यों का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने दिल्लीवासियों की सुख, शांति और समृद्धि की कामना भी की। हौज खास स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में आयोजित रथयात्रा में संतों, धर्मगुरुओं और हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी रही। नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज, कई विधायक भी मौजूद रहे। उपराज्यपाल ने रथयात्रा का शुभारंभ कर आयोजकों को इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ाने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह आयोजन भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। यह दिल्ली में भगवान जगन्नाथ की सबसे बड़ी यात्रा में से एक है। उपराज्यपाल ने कहा कि वार्षिक रथयात्रा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने बाहर निकलते हैं। यह सनातन धर्म की समावेशी भावना का प्रतीक है, जो बताती है कि ईश्वर की कृपा किसी भेदभाव को नहीं मानती और हर श्रद्धालु तक समान रूप से पहुंचती है। उन्होंने रथयात्रा से जुड़ी चेरा पहरा परंपरा का भी विशेष उल्लेख किया। एलजी ने कहा कि इस परंपरा में राजा भी भगवान के रथ के आगे मार्ग की सफाई करते हैं। यह संदेश देता है कि ईश्वर के सामने सभी समान हैं और सच्चा नेतृत्व सेवा तथा विनम्रता से ही स्थापित होता है। यही परंपरा समाज को अहंकार छोड़कर लोकसेवा का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देती है। उपराज्यपाल ने इस शुभ अवसर पर दिल्ली के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य, शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद सभी नागरिकों पर बना रहे और समाज में सौहार्द, भाईचारा तथा सेवा की भावना निरंतर मजबूत होती रहे।

सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- हर जिंदगी कीमती, दिया ये आदेश

नई दिल्ली । सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल 19वें दिन भी जारी है। लंबे समय से जारी इस हड़ताल के कारण उनका वजन 9 किलोग्राम से अधिक घट गया है। डॉक्टरों की टीम उनकी शारीरिक स्थिति पर लगातार निगरानी रख रही है। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की अदालत इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल के द्वारा दिए गए आश्वासन से हम संतुष्ट हैं। यह निर्देश दिए जाते हैं कि सरकारी डॉक्टरों द्वारा सोनम वांगचुक्की नियमित जांच की जाए और डॉक्टरों की सलाह पर उचित हस्तक्षेप किया जाए। अदालत ने जनहित याचिका का निस्तारण किया। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सोनम का स्वास्थ्य नियमित तौर पर चेक हो रहा है।

अदालत ने पूछा कि क्या सरकारी डॉक्टर सोनम वांगचुक की जांच कर रहे हैं। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि नहीं उनकी तरफ से जब भी हमें अनुमति जाएगी सरकारी डॉक्टर उनकी नियमित जांच करना शुरू कर देंगे।

तुषार मेहता ने अदालत को आश्वासन दिया कि अब सरकारी चिकित्सक उनकी नियमित जांच करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर उचित कदम उठाए जाएंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के आश्वासन के बाद अदालत ने कहा की प्रत्येक नागरिक का जीवन कीमती है। किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार अपने जीवन को अंत करने के लिए नहीं देखा जा सकता। डॉक्टरों के अनुसार, सोनम वांगचुक अभी भी काफी सक्रिय हैं। डॉक्टर सतीश लांबा ने उनके स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि लगातार उपवास से ब्लड शुगर का स्तर घट रहा है। इससे उनके स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ सकते हैं। कई बार उनसे भूख हड़ताल खत्म करने का आग्रह किया गया है। हालांकि, उन्होंने अपनी मांगों पर कार्रवाई न होने तक हड़ताल जारी रखने की बात कही है। कुछ देर में उनके स्वास्थ्य की फिर से जांच की जाएगी। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने एक्स हैंडल पर एक वीडियो साझा किया है। उन्होंने कहा कि उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत खराब भी नहीं है। डॉक्टर सतीश लांबा ने सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उपवास के कारण ब्लड शुगर का स्तर कम हो रहा है। यह स्थिति स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरी हो सकती है। डॉक्टरों की टीम उनकी शारीरिक स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। वांगचुक अभी भी काफी सक्रिय बने हुए हैं।

संसद मार्च का आह्वान

सोनम वांगचुक ने लोगों से 20 जुलाई को उनके साथ जुड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो संदेश जारी किया। इसमें उन्होंने संसद तक शांतिपूर्ण मार्च में शामिल होने के लिए कहा है। वांगचुक ने कहा कि उनसे व्रत तोड़ने के बजाय लोग उनके आंदोलन का समर्थन करें।

सम्पादकीय...

यू-टर्न

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा, जिसने न केवल अंतरराष्ट्रीय कूटनीति बल्कि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजारों में भी हलचल पैदा कर दी। ट्रंप ने घोषणा की थी कि होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले सभी मालवाहक जहाजों पर अमेरिका 20 प्रतिशत टोल लगाएगा। हालांकि इस घोषणा के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया। इस घटनाक्रम ने अमेरिका की विदेश नीति, वैश्विक समुद्री कानून और खाड़ी देशों के साथ उसके संबंधों को लेकर कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर घोषणा करते हुए कहा कि अब से होर्मुज को 'द गार्जियन ऑफ द होर्मुज स्ट्रेट' के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने दावा किया कि वर्षों से अमेरिका इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करता आया है, इसलिए यहां से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों से 20 प्रतिशत शुल्क लिया जाना उचित होगा। ट्रंप का तर्क था कि वैश्विक समुद्री व्यापार की सुरक्षा में अमेरिका की भूमिका के बदले उसे आर्थिक प्रतिफल मिलना चाहिए। होर्मुज जलडमरूमध्य विश्व के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला यह संकरा जलमार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की जीवनरेखा माना जाता है। दुनिया के कुल समुद्री कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोप के कई देश अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए इस मार्ग पर अत्यधिक निर्भर हैं। ऐसे में यहां किसी भी प्रकार की नई आर्थिक या राजनीतिक व्यवस्था का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। ट्रंप की घोषणा के तुरंत बाद व्हाइट हाउस के भीतर भी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारी यह समझने की कोशिश करते रहे कि इस टोल व्यवस्था को लागू कैसे किया जाएगा। यह स्पष्ट नहीं था कि शुल्क कौन देगा—जहाज मालिक, शिपिंग कंपनियां, आयातक देश या अमेरिका के सहयोगी खाड़ी राष्ट्र। इसके अलावा यह भी तय नहीं था कि शुल्क की वसूली किस कानूनी व्यवस्था के तहत होगी और इसका संचालन कौन करेगा। उधर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कतर जैसे प्रमुख खाड़ी देशों ने इस प्रस्ताव पर गंभीर चिंता व्यक्त की। इन देशों के नेताओं ने तत्काल अमेरिकी राष्ट्रपति से संपर्क साधने का प्रयास किया और उन्हें इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। उनका मानना था कि यदि यह टोल लागू होता है तो इससे क्षेत्रीय व्यापार, तेल निर्यात और वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। खाड़ी देशों के कूटनीतिक प्रयास सफल रहे। अगले ही दिन राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने फैसले से पीछे हटते हुए घोषणा की कि फिलहाल इस टोल को लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों ने जहाजों से शुल्क देने के बजाय अमेरिका में निवेश बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। ट्रंप ने कहा कि विभिन्न देशों के राजाओं, अमीरों और नेताओं से उनकी बातचीत हुई और एक वैकल्पिक समाधान सुझाया, जिसे उन्होंने बेहतर विकल्प माना। व्हाइट हाउस के अधिकारियों के अनुसार, ट्रंप का उद्देश्य अमेरिका द्वारा वर्षों से प्रदान की जा रही समुद्री सुरक्षा के बदले आर्थिक लाभ प्राप्त करना था। लेकिन जब सहयोगी देशों ने अमेरिका में अतिरिक्त निवेश करने की सहमति जताई, तो राष्ट्रपति ने टोल योजना को वापस लेने का निर्णय लिया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान ट्रंप के अपने सलाहकार भी इस प्रस्ताव के विरोध में थे। रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने कई महीनों से राष्ट्रपति को चेतावनी दी थी कि ऐसा कदम अमेरिका के दीर्घकालिक हितों के विपरीत होगा। उनका मानना था कि इस प्रकार का शुल्क वैश्विक तेल और गैस की कीमतों को बढ़ा सकता है, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं पर महंगाई का दबाव बढ़ेगा। इसके अलावा आगामी मध्यावधि चुनावों से पहले यह राजनीतिक रूप से भी नुकसानदायक साबित हो सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अमेरिका लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में मुक्त नौवहन का समर्थक रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कुछ सप्ताह पहले ही स्पष्ट रूप से कहा था कि किसी भी देश को अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क लगाने का अधिकार नहीं है। यह अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के विरुद्ध है। ऐसे में ट्रंप का प्रस्ताव स्वयं अमेरिका की वर्षों पुरानी आधिकारिक नीति से मेल नहीं खाता था। इस विवाद का एक और महत्वपूर्ण पहलू ईरान की प्रतिक्रिया रही। ईरान लंबे समय से यह दावा करता रहा है कि यदि कोई देश होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, तो उसे इसके बदले उचित आर्थिक लाभ मिलना चाहिए। ट्रंप के बयान को ईरान ने अपने पक्ष के समर्थन के रूप में प्रस्तुत किया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यदि कोई देश इस समुद्री मार्ग की सुरक्षा करता है, तो उसे इसके लिए मुआवजा मिलना चाहिए। हालांकि उन्होंने व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि 20 प्रतिशत शुल्क बहुत अधिक है और यदि कभी ऐसी व्यवस्था बनी, तो ईरान इससे कम और 'उचित' शुल्क लगाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का यह प्रस्ताव भले ही लागू नहीं हुआ, लेकिन इसने वैश्विक समुद्री सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय कानून को लेकर नई बहस छेड़ दी है। यदि भविष्य में कोई भी शक्तिशाली देश अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों पर शुल्क लगाने का प्रयास करता है, तो इससे वैश्विक व्यापार व्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून का मूल सिद्धांत यह है कि ऐसे जलमार्ग सभी देशों के लिए खुले और स्वतंत्र रहें। भारत जैसे देशों के लिए भी यह घटनाक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है और उसका अधिकांश तेल होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर ही आता है। यदि इस मार्ग पर किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क या अस्थिरता उत्पन्न होती है, तो इसका सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा, आयात लागत और महंगाई पर पड़ सकता है। कुल मिलाकर, होर्मुज जलडमरूमध्य पर टोल लगाने का ट्रंप का प्रस्ताव भले ही एक दिन के भीतर वापस ले लिया गया हो, लेकिन इसने यह स्पष्ट कर दिया कि पश्चिम एशिया की बदलती परिस्थितियों में समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक व्यापार अब पहले से कहीं अधिक संवेदनशील मुद्दे बन चुके हैं। आने वाले समय में अमेरिका, ईरान और खाड़ी देशों के बीच होने वाले कूटनीतिक फैसले न केवल क्षेत्रीय स्थिरता बल्कि पूरी विश्व अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

रोजगार लायक शिक्षा के लिए पुराने डिग्री ढर्रे में बदलाव जरूरी

चीन के अखबार साऊथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक हालिया रिपोर्ट चीनी शिक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए बड़े बदलाव की बात करती है, कि कैसे चीन ने 2021 से 2025 के बीच आर्टस, ह्यूमैनिटी, मैनेजमेंट और विदेशी भाषाओं के 12,200 डिग्री कोर्स बंद करके आर्टिफिशियल इंटेलीजैंस (ए.आई.), रोबोटिक्स, चिप उत्पादन, सैमीकंडक्टर और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के 10,200 नए कोर्स शुरू किए, क्योंकि इन क्षेत्रों में भी चीन अपनी ग्लोबल लीडरशिप मजबूत करना चाहता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आर्थिक मंदी, ऑटोमेशन और कुछ क्षेत्रों में पेशेवरों की जरूरत से अधिक उपलब्धता होने के कारण चीन ने उच्च शिक्षा को सीधे औद्योगिक नीति के साथ जोड़ने के लिए शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की पहल की है। चीन की इच्छा यह भी है कि देश में डिग्रीधारी लाखों बेरोजगार युवाओं की भीड़ न बढ़े। चीन की यह पहल भारत के लिए भी एक बड़ा सबक है, जिसे लंबे समय तक नहीं टाला जा सकता। जब डिग्रियां नौकरी नहीं दे पातीं तो शिक्षा व्यवस्था में बदलाव समय की मांग है। रोजगार लायक न रहने के बावजूद पुराने डिग्री ढांचे को बनाए रखने की बजाय भारत को भी अपने मानव संसाधनों को इन क्षेत्रों की तरफ मोड़ना होगा, जो बेरोजगारी से लड़ने व आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। खतरे में डिग्रियां : अगर भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था चीन की सोच को ईमानदारी से लागू करे तो यहां भी अगले कुछ ही सालों में बहुत से डिग्री कोर्स बंद करने की जरूरत है। इतिहास व दर्शन शास्त्र जैसे विषय आज के समय में रोजगार लायक नहीं सिर्फ ज्ञान के लिए बचे हैं। साधारण बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम, एम.ए., बी.एड, बी.बी.ए., बी.सी.ए., बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के लिए रोजगार की संभावनाएं लगभग खत्म होती जा रही हैं। कॉमर्स, बी.बी.ए., कला और फोटोग्राफी डिप्लोमा व कई प्राइवेट कॉलेजों के इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी खतरे के जोन में हैं। यहां तक कि एम.बी.ए. की डिग्री भी दबाव में है, क्योंकि कंपनियां लेबल की बजाय हुनर को अहमियत दे रही हैं। उन डिग्री कोर्स को प्रोत्साहित किया जाए जिनमें भविष्य के रोजगार की क्षमता हो। डिग्री हासिल करने वालों की संख्या देश में उपलब्ध रोजगार से कहीं अधिक है। हर साल डिग्री कोर्स में रिकॉर्ड दाखिलों के पीछे बेरोजगारी की कड़ी चुनौती छुपी है। बी.टैक, जो कभी भारतीय उच्च शिक्षा का मुकुट मणि थी, आज 30 से 44 प्रतिशत सीटें खाली हैं। मंजूरशुदा 15.40 लाख सीटों में से हर साल 5 से 6 लाख से सीटें खाली रहती हैं। बढ़ती खाली सीटों के कारण ऑल इंडिया कौंसिल फॉर टैक्नीकल एजुकेशन (ए.आई.सी.टी.ई.) ने वर्ष 2025 में देशभर में 58 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद कराए व सिविल, मैकेनिकल और इलैक्ट्रिकल जैसे 950 से अधिक कोर्स भी बंद हुए। हर 3 में से 2 एम.टैक सीटें खाली हैं। कम्प्यूटर साइंस, ए.आई. और डाटा साइंस के युग में मैकेनिकल, सिविल और इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए रोजगार के अवसर तेजी से घटे हैं। यह विकास का संकेत नहीं, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा बड़ा बदलाव है, जिसे ए.आई., रोबोटिक्स व ऑटोमेशन तेजी से बदल रहे हैं।

हुनर ने ली डिग्री की जगह : ए.आई.सी.टी.ई. और इंडियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन द्वारा हाल ही में जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट एक कड़वी सच्चाई उजागर करती है कि 72 प्रतिशत ग्रैजुएट और 58 प्रतिशत बिजनैस स्कूलों के सिलेबस उद्योगों की प्रैक्टिकल जरूरत से मेल नहीं खाते। भर्तीकर्ताओं ने अपने भर्ती फैसलों से बताया है कि उनमें से करीब दो-तिहाई एम्पलायर्स अब ए.आई., मशीन लर्निंग, डाटा साइंस और साइबर सुरक्षा में हुनरमंद उम्मीदवारों को कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ब्रांड की परवाह किए बगैर प्रीमियम प्रतिभा मानते हैं, जबकि मुश्किल से एक-तिहाई कंपनियां को भर्ती के लिए अब भी आई.आई.टी. या आई.आई.एम. टैग की परवाह है। भर्तियां अब डिग्री सर्टीफिकेट से आगे पोर्टफोलियो, माइक्रो-क्रेडेंशियल और स्टैकेबल सर्टिफिकेशन की तरफ बढ़ रही हैं। कंपनियों को अब काबिलियत का असली सबूत चाहिए, न कि डिग्री या डिप्लोमा। आज के दिन कम्प्यूटर साइंस, आई.टी. और ए.आई. ग्रैजुएट की रोजगार योग्यता 80 प्रतिशत के करीब है, जबकि स्पैशल कॉमर्स ग्रैजुएट के लिए बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं, बीमा और फिनटेक सैक्टर में मांग की बदौलत रोजगार के अवसर 62 प्रतिशत हैं। पॉलिटैक्निक डिप्लोमा धारक 33 प्रतिशत पर अटके हैं, जबकि आई.टी.आई. की रोजगार योग्यता 46 व पॉलिटैक्निक की 33 प्रतिशत पर सिमट गई है। आगे की राह : इससे पहले कि पूरी एक युवा पीढ़ी के पास रोजगार की बजाय दिखाने के लिए फ्रेम में लगा एक सर्टिफिकेट ही बचे, भारत को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए समय रहते ठोस कदम उठाने होंगे। सुधार के इन तीन अहम कदमों में पहला, ए.आई. और डाटा साक्षरता को हर डिग्री कोर्स में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए, ताकि वर्कफोर्स में हर साल शामिल होने वाले 1 करोड़ से अधिक लोग ए.आई. पर शासन कर सकें, न कि ए.आई. उन पर। यह पहला कदम अगले दोनों कदमों की बुनियाद तैयार करता है। दूसरा, हर 5 साल बाद ऑल इंडिया कौंसिल फॉर टैक्नीकल एजुकेशन और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यू.जी.सी.) एवं राज्य सरकारें मिलकर हरेक डिग्री कोर्स की बाजार में मांग का ऑडिट करें, लगातार कम प्लेसमैंट व खाली सीटों वाले कोर्सों को बंद करने पर विचार हो। तीसरा, फैकल्टी के लिए ए.आई. टूल्स की ट्रेनिंग, उद्योग जगत से जुड़े एक्सपर्ट्स को प्रोफैसर ऑफ प्रैक्टिस के तौर पर यूनिवर्सिटीज व कॉलेजों से जोड़ा जाए, वरना उच्च शिक्षा में सुधार की कवायद केवल कागजी साबित होगी।

मर्यादा

अक्सर सुना जाता है कि अधिकतर बेटे समय के साथ बदल जाते हैं। मां-बाप की सेवा नहीं करते, उन्हें अंतिम समय में तंग करते हैं या प्रोपर्टी के लिए झगड़ा करते हैं परन्तु आज जब पिछले लगभग 24 सालों से मैं बुजुर्गों के लिए काम कर रही हूं तो जहां बेटियां अच्छे कार्यों में बेटों से कम नहीं, वहां कुछ बेटियां बुरे कामों में भी कुछ बुरे बेटों से कम नहीं। मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि बेटियां तो कभी ऐसी नहीं होती थीं, क्योंकि बेटियां तो हमारे देश में पूजी जाती हैं। जहां कन्या को देवी का रूप माना... अक्सर सुना जाता है कि अधिकतर बेटे समय के साथ बदल जाते हैं। मां-बाप की सेवा नहीं करते, उन्हें अंतिम समय में तंग करते हैं या प्रोपर्टी के लिए झगड़ा करते हैं परन्तु आज जब पिछले लगभग 24 सालों से मैं बुजुर्गों के लिए काम कर रही हूं तो जहां बेटियां अच्छे कार्यों में बेटों से कम नहीं, वहां कुछ बेटियां बुरे कामों में भी कुछ बुरे बेटों से कम नहीं। मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि बेटियां तो कभी ऐसी नहीं होती थीं, क्योंकि बेटियां तो हमारे देश में पूजी जाती हैं। जहां कन्या को देवी का रूप माना जाता है, जहां गार्गी, मैत्रेयी, रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होल्कर और कल्पना चावला जैसी महान बेटियां हुई हैं। लेकिन आज जब समाचारों में सुनती हूं कि कहीं कोई बेटी अपने माता-पिता के साथ क्रूरता करती है, कहीं रिश्तों को लालच और स्वार्थ के लिए तोड़ा जा रहा है। कहीं गलत संगत और क्षणिक क्रोध में अपराध हो रहे हैं। अभी-अभी सुना कि एक बेटी ने अपनी मां को मार दिया। कुछ दिनों पहले एक बेटी ने अपने मंगेतर को विवाह से पहले मार दिया। कई नई विवाहित महिलाओं ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। आखिर हम कहां जा रहे हैं। हमारे संस्कार, हमारे रिश्तों की मर्यादा कहां जा रही है। मैं सभी बेटियों को दोष नहीं देती। आज भी हमारी लाखों-करोड़ों बेटियां अपने माता-पिता की समर्पित भाव से सेवा कर रही हैं। विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर रही हैं और हर क्षेत्र में सफलता के नए इतिहास लिख रही हैं। लेकिन जो बेटियां गलत रास्ते पर जा रही हैं उनसे मैं हाथ जोड़कर कहना चाहती हूं, बेटियां कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार अपनी मां का चेहरा याद कर लेना। वह बचपन याद कर लेना, जब तुम्हारी एक छोटी-सी चोट पर तुम्हारे माता-पिता की आंखों में आंसू आ जाते थे। जिस मां ने तुम्हें नौ महीने अपनी कोख में रखा, जिस पिता ने तुम्हारे सपनों के लिए अपनी इच्छाएं त्याग दीं उनका दिल कभी मत दुखाना। आधुनिक बनो, आगे बढ़ो, अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो, आसमान छुओ लेकिन अपनी जड़ों और संस्कारों को मत भूलो। आजादी का अर्थ मनमानी नहीं है। आधुनिकता का अर्थ रिश्तों को भूल जाना नहीं है और अधिकारों के साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं। बेटियों तुम शक्ति हो, तुम ममता हो, तुम संस्कार हो, तुम घर की रौनक हो और समाज का भविष्य हो। ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे तुम्हारे माता-पिता को दुनिया के सामने सिर झुकाना पड़े। ऐसा जीवन जियो कि वे गर्व से कहें "हां यह हमारी बेटी है।" तुम बेटी हो उड़ो, खूब ऊंचा उड़ो लेकिन अपनी जड़ों को मत भूलो। दुनिया को बदलो, लेकिन अपने संस्कार मत बदलो। आधुनिक बनो, आत्मनिर्भर बनो, शक्तिशाली बनो लेकिन इंसानियत, ममता और रिश्तों की मर्यादा को हमेशा अपने दिल में जीवित रखो। क्योंकि बेटी केवल एक परिवार की पहचान नहीं बेटी समाज का संस्कार और राष्ट्र का भविष्य है। बेटी सशक्त संस्कारवान होगी तो परिवार सशक्त संस्कारवान होगा, परिवार सशक्त संस्कारवान होगा तो समाज भी सशक्त होगा, समाज होगा तो देश भी सशक्त और संस्कारवान होगा। क्योंकि एक बेटी किसी भी रूप में परिवार की धुरी होती है। अभी मैं लिख ही रही थी कि एक हमारी सदस्या अपनी कलियुगी बेटी की समस्या लेकर आई है।

मुख्यमंत्री आवास योजना से आजमगढ़ में पक्के आशियानों के साकार होते सपने

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आवास विहीन और अत्यंत असुरक्षित परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए 'मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)' का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। इस कल्याणकारी पहल के अंतर्गत ग्रामीण उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों को प्राकृतिक आपदाओं, विशिष्ट सामाजिक श्रेणियों और गंभीर स्वास्थ्य निर्योग्यताओं के प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए पक्के मकानों की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में जनपद आजमगढ़ ने योजना के क्रियान्वयन में एक मिसाल पेश की है, जहां 96.23 प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति के साथ हजारों परिवारों को कच्ची दीवारों से निकालकर पक्के घरों तक पहुंचाया गया है। यह उपलब्धि केवल प्रशासनिक आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि ग्रामीण स्तर पर सामाजिक गरिमा, सुरक्षा और महिला सशक्तीकरण की एक नई इबारत है। जनपद आजमगढ़ को योजना के अंतर्गत कुल 9,908 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसके सापेक्ष जिला प्रशासन ने तीव्र और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए 9,534 आवास पूर्ण कर लाभार्थियों को हस्तांतरित कर दिए हैं। प्रदेश के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जनपदों में आजमगढ़ की यह मजबूत प्रशासनिक कार्यशैली प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को धरातल पर उतारने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासन द्वारा मासिक समीक्षा बैठकों, निर्माण कार्यों की सतत निगरानी, पारदर्शी लाभार्थी चयन तथा विभिन्न योजनाओं के प्रभावी अभिसरण (कन्वर्जेंस) पर विशेष बल दिया गया। इसी रणनीतिक दृष्टिकोण के कारण आजमगढ़ आज पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के सफल क्रियान्वयन का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन पात्र परिवारों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है, जो किन्हीं कारणों से केंद्र सरकार की आवास योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए थे। शासन द्वारा जारी नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुरूप, योजना के तहत उन वर्गों को प्राथमिकता दी गई जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हैं। इनमें प्राकृतिक आपदा (बाढ़, अग्निकांड या भूकंप) से प्रभावित परिवार, कुष्ठ रोग, जापानी इंसेफेलाइटिस (जेई), एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम तथा कालाजार जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित परिवार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मुसहर समुदाय, वनटांगिया, कोल, सहरिया जैसी वंचित अनुसूचित जनजातियों, विधवा महिलाओं, दिव्यांगजनों तथा आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर वर्गों को इसमें विशेष वरीयता दी गई है। सामाजिक न्याय और महिला सशक्तीकरण के सिद्धांतों को सुदृढ़ करते हुए इन आवासों का पंजीकरण मुख्य रूप से परिवार की महिला मुखिया के नाम पर अथवा पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर सुनिश्चित किया गया है, जिससे ग्रामीण परिवेश में महिलाओं के आत्मसम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि हुई है। योजना के तकनीकी एवं वित्तीय प्रावधानों के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मैदानी क्षेत्रों में प्रति आवास ₹1.20 लाख तथा कठिन या पथरीले क्षेत्रों में ₹1.30 लाख की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जा रही है। निर्मित होने वाले प्रत्येक आवास का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है, जिसमें दो कमरों के साथ स्वच्छ रसोईघर, आधुनिक स्नानघर और एक सुसज्जित शौचालय की सुविधा शामिल है। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए संपूर्ण चयन प्रक्रिया सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों (ईएसी) तथा ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापित 'आवास प्लस' सूची के आधार पर संचालित की जा रही है, जिससे केवल वास्तविक रूप से जरूरतमंद और भूमिहीन परिवारों तक ही इस सरकारी सहायता की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका बहुआयामी 'अभिसरण मॉडल' है, जो इसे केवल आवास निर्माण तक सीमित न रखकर समग्र ग्रामीण विकास का माध्यम बनाता है। इसके तहत प्रत्येक पात्र परिवार को 1,20,000 की प्रत्यक्ष आवासीय सहायता के साथ-साथ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के माध्यम से 90 दिवस की अकुशल मजदूरी प्रदान की जाती है, जिससे निर्माण अवधि के दौरान परिवार को आय का अतिरिक्त सहारा मिलता है। इसके अतिरिक्त, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ₹12,000 की लागत से शौचालय का निर्माण कराया जाता है। लाभार्थी परिवारों को पात्रतानुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन, सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युत कनेक्शन तथा हर घर जल योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। एक ही छत के नीचे इतनी सुविधाओं का समागम ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार ला रहा है। आजमगढ़ के जहानागंज विकास खण्ड के सेमा गांव की रहने वाली गुड्डी की कहानी इस योजना की सफलता का एक जीवंत प्रमाण है। अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाली गुड्डी और उनके पति दुर्गेश वर्षों से दैनिक मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण कर रहे थे। अत्यंत सीमित आय के कारण उनका पक्का घर बनाने का सपना अधूरा था और पूरा परिवार एक जर्जर कच्चे मकान में रहने को मजबूर था। मिट्टी की दीवारें बारिश में गल जाती थीं, छत हर वर्ष टपकती थी और तेज हवाओं व विपरीत मौसम में पूरा परिवार भय के साये में रात गुजारता था। बरसात के दिनों में बच्चों की पढ़ाई ठप हो जाती थी क्योंकि किताबों और जरूरी सामानों को भीगने से बचाना ही सबसे बड़ी चुनौती थी।

मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत चयन होने के बाद गुड्डी के परिवार का जीवन पूरी तरह बदल गया है। उन्हें मिले पक्के मकान, शौचालय और अन्य सरकारी लाभों ने न केवल उन्हें मौसम की मार से सुरक्षा दी है, बल्कि समाज में उनका गौरव भी बढ़ाया है। गुड्डी की तरह ही आजमगढ़ के हजारों लाभार्थियों के लिए यह योजना केवल ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा, स्वच्छता और आत्मविश्वास से भरे नए जीवन की शुरुआत है। अब इन परिवारों को हर मौसम में घर टूटने या भीगने का डर नहीं रहता और उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास विहीन और कमजोर वर्गों को दी गई यह पक्की छत आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की नींव को और मजबूत कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की इस संवेदनशील और विकासोन्मुखी पहल ने आजमगढ़ में एक ऐसी मौन क्रांति को जन्म दिया है, जिसने न केवल गरीब परिवारों को एक सुरक्षित आशियाना दिया है, बल्कि उनके सपनों को भी एक नया और खुला आसमान प्रदान किया है।

> **मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत चयन होने के बाद गुड्डी के परिवार का जीवन पूरी तरह बदल गया है। उन्हें मिले पक्के मकान, शौचालय और अन्य सरकारी लाभों ने न केवल उन्हें मौसम की मार से सुरक्षा दी है, बल्कि समाज में उनका गौरव भी बढ़ाया है। गुड्डी की तरह ही आजमगढ़ के हजारों लाभार्थियों के लिए यह योजना केवल ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा, स्वच्छता और आत्मविश्वास से भरे नए जीवन की शुरुआत है। अब इन परिवारों को हर मौसम में घर टूटने या भीगने का डर नहीं रहता और उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास विहीन और कमजोर वर्गों को दी गई यह पक्की छत आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की नींव को और मजबूत कर रही है।**

ललितपुर : जाम से मिली मुक्ति और विकास को मिली नई रफ्तार

किसी भी प्रदेश की प्रगति उसकी मजबूत आधारभूत संरचना से पहचानी जाती है। बेहतर सड़कें, आधुनिक पुल और सुगम यातायात व्यवस्था केवल आवागमन को आसान ही नहीं बनाते, बल्कि व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति प्रदान करते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेशभर में आधुनिक एवं सुरक्षित सड़क अवसंरचना के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में जनपद ललितपुर में पुलों एवं रेलवे ओवरब्रिजों के निर्माण ने वर्षों पुरानी यातायात समस्याओं का समाधान करते हुए विकास की एक नई इबारत लिखी है। आज जिन मार्गों पर कभी घंटों जाम, जलभराव और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता था, वहीं अब लोगों को सुरक्षित, तेज और निर्बाध आवागमन की सुविधा मिल रही है।

लंबे समय तक ललितपुर शहर के अनेक प्रमुख मार्ग संकरे पुलों, रेलवे फाटकों और बरसात के दौरान जलभराव जैसी समस्याओं से प्रभावित रहे। आम नागरिकों, विद्यार्थियों, किसानों, व्यापारियों, मरीजों और दैनिक यात्रियों को प्रतिदिन भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कई बार लोगों का महत्वपूर्ण समय जाम में ही बीत जाता था, जिससे आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित होती थीं। आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों और एम्बुलेंस को भी समय पर अस्पताल पहुंचने में परेशानी होती थी। इन चुनौतियों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने शहर की आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक पुलों और रेलवे ओवरब्रिजों के निर्माण को प्राथमिकता देते हुए निर्माण कराया है।

ब्यानमाला पुल बना सुगम यातायात का नया आधार

ललितपुर शहर के प्रमुख मार्ग पर स्थित ब्यानमाला का पुराना पुल लंबे समय से लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ था। पुल इतना संकरा था कि दो बड़े वाहनों का एक साथ निकलना संभव नहीं हो पाता था, जिसके कारण दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती थी। वर्ष 2022 में इस पुल के चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया। अब आधुनिक तकनीक से निर्मित नया पुल अधिक चौड़ा, मजबूत और सुरक्षित बन चुका है। दोनों दिशाओं में वाहनों का आवागमन बिना किसी बाधा के हो रहा है तथा वर्षा ऋतु में भी यातायात सामान्य बना रहता है। इससे हजारों लोगों का समय बच रहा है और शहर की यातायात व्यवस्था पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सुचारू हो गई है।

कैलगुवां रेलवे ओवरब्रिज से दुर्घटनाओं पर लगा अंकुश

कैलगुवां चौराहे के निकट रेलवे फाटक लंबे समय तक जाम और दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बना रहा। फाटक बंद होने पर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती थीं, जिससे यात्रियों को काफी समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के बाद अब वाहनों का आवागमन पूरी तरह निर्बाध हो गया है। लोगों का बहुमूल्य समय बच रहा है, सड़क सुरक्षा में सुधार हुआ है तथा दुर्घटनाओं की संभावनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। यह परियोजना आधुनिक आधारभूत संरचना के माध्यम से जनसुविधा बढ़ाने का प्रभावी उदाहरण बनकर सामने आई है।

शहजाद नदी पर आधुनिक पुल से हर मौसम में सुगम आवागमन

शहर में शहजाद नदी पर स्थित ब्रिटिश कालीन पुल वर्षों से अपनी सीमित क्षमता के कारण लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था। संकरा होने के साथ-साथ बरसात के दिनों में जलभराव के कारण कई बार आवागमन पूरी तरह बाधित हो जाता था। प्रदेश सरकार द्वारा यहां आधुनिक और अधिक क्षमता वाले नए पुल का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। इसके पूर्ण होने के बाद नागरिकों को वर्षभर सुरक्षित और निर्बाध यातायात की सुविधा प्राप्त होगी। साथ ही क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी।

खिरकापुरा पुल से ग्रामीण क्षेत्रों को मिली नई राह

बानपुर, टीकमगढ़ और महरौनी क्षेत्र से आने-जाने वाले हजारों लोगों के लिए खिरकापुरा का पुराना पुल वर्षों तक बड़ी चुनौती बना रहा। पुल संकरा और नीचा होने के कारण विशेषकर बरसात में यातायात बाधित हो जाता था और लोगों को कई किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती थी। नए पुल के निर्माण के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क अधिक सुदृढ़ हुआ है। किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में सुविधा मिली है, विद्यार्थियों की आवाजाही आसान हुई है और स्थानीय लोगों का समय तथा परिवहन व्यय कम हुए हैं।

देवगढ़ रेलवे ओवरब्रिज बना क्षेत्रीय विकास का नया द्वार

देवगढ़ मार्ग पर स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर प्रतिदिन हजारों लोगों को रेलवे फाटक खुलने की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। लगभग 30 हजार की आबादी तथा 50 से अधिक गांवों के लोग इस समस्या से प्रभावित थे। दिल्ली-मुंबई रेलमार्ग पर ट्रेनों की अधिक आवाजाही के कारण जाम की स्थिति और गंभीर हो जाती थी। रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के बाद अब लोगों को बिना रुके सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल रही है। इससे न केवल यातायात व्यवस्था में सुधार हुआ है, बल्कि व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और ग्रामीण-शहरी संपर्क को भी नई गति मिली है।

सिर्फ पुल नहीं, विकास की नई आधारशिला

ललितपुर में निर्मित पुलों और रेलवे ओवरब्रिजों ने केवल आवागमन को ही आसान नहीं बनाया, बल्कि विकास की नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। जाम से राहत मिलने के कारण ईंधन की बचत हो रही है, यात्रा का समय कम हुआ है और सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आई है। व्यापारिक गतिविधियों को गति मिली है, किसानों को अपनी उपज समय पर मंडियों तक पहुंचाने में सुविधा हुई है तथा विद्यार्थियों और मरीजों के लिए भी यात्रा पहले की अपेक्षा अधिक सुरक्षित और आसान बनी है। मजबूत आधारभूत संरचना का यह विकास स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य केवल सड़क और पुलों का निर्माण ही करना नहीं है, बल्कि ऐसी आधुनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करना है जो नागरिकों के जीवन को सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाए।

इसी सोच के साथ प्रदेशभर में सड़क संपर्क, रेलवे ओवरब्रिज, सेतु निर्माण और अन्य आधारभूत परियोजनाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है, जिससे विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। आज ललितपुर के ये पुल और ओवरब्रिज केवल कंक्रीट और स्टील की संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि जनसुविधा, सुशासन और समग्र विकास के सशक्त प्रतीक बन चुके हैं। यह परिवर्तन दर्शाता है कि दूरदर्शी योजना, गुणवत्तापूर्ण निर्माण और समयबद्ध क्रियान्वयन के माध्यम से वर्षों पुरानी समस्याओं का स्थायी समाधान संभव है। सुरक्षित और सुगम यातायात की यह नई व्यवस्था विकसित उत्तर प्रदेश की मजबूत आधारभूत संरचना और जनकल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का जीवंत उदाहरण है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने वन्दना ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, सावा पॉलिटेक्निक एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो० : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2016/68863)

सांसद के निर्देश पर पटहेरिया-तुर्कपट्टी मार्ग पर चला सफाई अभियान

पटहेरवा/कुशीनगर।

पटहेरिया-तुर्कपट्टी मुख्य मार्ग पर सड़क किनारे उगी झाड़ियों और अवरोधों को हटाने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने विशेष सफाई अभियान चलाया। यह कार्रवाई देवरिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद शशांक मणि त्रिपाठी के निर्देश पर की गई। जानकारी के अनुसार, भाजपा पटहेरवा मंडल महामंत्री अभिषेक तिवारी ने सड़क किनारे उगी घनी झाड़ियों, अतिक्रमण और दुर्घटना की आशंका को लेकर सांसद को प्रार्थना पत्र सौंपा था। इसके बाद सांसद ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से वार्ता कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। निर्देश मिलते ही पीडब्ल्यूडी की टीम जेसीबी मशीन के साथ मौके पर पहुंची और पटहेरिया से तुर्कपट्टी तक सड़क किनारे उगी झाड़ियों, बेलों एवं अन्य अवरोधों को हटाने का कार्य शुरू किया। अभियान के बाद मार्ग पहले की तुलना में अधिक साफ और सुरक्षित दिखाई देने लगा। भाजपा जिलाध्यक्ष के अनुसार, इस अभियान में पटहेरवा मंडल अध्यक्ष अमलेश तिवारी ने भी अधिकारियों से समन्वय बनाए रखते हुए स्थानीय स्तर पर कार्य की निगरानी की। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं और अन्य राहगीर गुजरते हैं।

पटहेरिया-तुर्कपट्टी मार्ग पर सांसद शशांक मणि त्रिपाठी के निर्देश पर जेसीबी मशीन से सड़क किनारे उगी झाड़ियों की सफाई करते पीडब्ल्यूडी कर्मी।

बरसात के दौरान सड़क किनारे झाड़ियां बढ़ जाने से सामने से आने वाले वाहन दिखाई नहीं देते थे, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती थी। सफाई अभियान शुरू होने के बाद क्षेत्र के लोगों ने राहत जताते हुए सांसद और पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया।

दिव्यांग छात्राओं को मिलेगी निःशुल्क ई-ट्राईसाइकिल, आवेदन आमंत्रित

कुशीनगर। उत्तर प्रदेश शासन की नई नियमावली-2026 के तहत स्कूल जाने वाली एवं शिक्षण/प्रशिक्षण प्राप्त कर रही पात्र दिव्यांग छात्राओं को निःशुल्क ई-ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने पात्र छात्राओं से आवेदन करने की अपील की है। योजना के तहत मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पाल्सी, हीमोफीलिया सहित अन्य पात्र दिव्यांग छात्राएं आवेदन कर सकती हैं। आवेदिका की दृष्टि एवं मानसिक स्थिति सामान्य हो, कमर के ऊपर का भाग स्वस्थ हो तथा वह अपने हाथों से ई-ट्राईसाइकिल संचालित करने में सक्षम होनी चाहिए। आवेदिका की आयु 16 वर्ष या उससे अधिक, जनपद की स्थायी निवासी तथा परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 1.80 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है। योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी अधिकतम 65 हजार रुपये तक की ई-ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई जाएगी। जिन छात्राओं को शिक्षण संस्थान की ओर से आवागमन की सुगम सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। लाभार्थियों का चयन 'प्रथम आवक, प्रथम पावक' के सिद्धांत पर जनपद स्तरीय तकनीकी समिति की संस्तुति के बाद किया जाएगा। आवेदन के साथ दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय, निवास एवं अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र, यूडीआईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार का नवीन फोटो, मोबाइल नंबर तथा आवश्यकतानुसार जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने पात्र दिव्यांग छात्राओं एवं उनके अभिभावकों से समय रहते आवश्यक अभिलेखों सहित आवेदन प्रस्तुत कर योजना का लाभ उठाने की अपील की है।

जननी सुरक्षा योजना के भुगतान में सुस्ती पर भड़के जिलाधिकारी, दिए कड़े निर्देश

हेपेटाइटिस-बी टीकाकरण में सुस्ती पर एमओआईसी को अल्टीमेटम

देवरिया। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चिकित्सा तंत्र को सुदृढ़ करने तथा स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जननी सुरक्षा योजना के लंबित भुगतानों, संस्थागत प्रसव की स्थिति, हेपेटाइटिस-बी टीकाकरण के कवरेज और सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की बुनियादी व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत का बारीकी से मिलान किया गया। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत होने वाले वित्तीय भुगतानों में कतिपय ब्लॉकों की धीमी प्रगति पर असंतोष जताया। उन्होंने सभी चिकित्सा अधीक्षकों (एमओआईसी) को दोटूक निर्देश दिए कि किसी भी ब्लॉक में भुगतान की प्रगति 80 प्रतिशत से नीचे नहीं होनी चाहिए, अन्यथा संबंधित की जवाबदेही तय की जाएगी। इसके साथ ही, सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव का ग्राफ बढ़ाने और नवजातों को हेपेटाइटिस-बी का सुरक्षा कवच समय से देने के लिए विशेष कार्ययोजना के तहत काम करने को कहा गया। शिशु और मातृ स्वास्थ्य को स्वास्थ्य विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए जिलाधिकारी ने सभी अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (एसीएमओ) और एमओआईसी को 1 जुलाई से 21 जुलाई तक की अवधि के आईएमआर (शिशु मृत्यु दर) तथा एमएमआर (मातृ मृत्यु दर) के अद्यतन आंकड़े तीन दिनों के भीतर पटल पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनपद में होने वाली प्रत्येक मातृ एवं शिशु मृत्यु का अनिवार्य रूप से समयबद्ध 'डेथ ऑडिट' कराया जाए, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में रहने वाली कमियों को दूर किया जा सके। जिलाधिकारी ने कड़े लहजे में कहा कि आमजन की सेहत से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर की शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिला स्तरीय स्वास्थ्य अधिकारी उपस्थित रहे।

वारंटी शमशुद्दीन को माननीय न्यायालय रवाना किया गया

एक नफर वारंटी गिरफ्तार

आन्दनगर ,महराजगंज। जनपद में वांछित अभियुक्तों एवं वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में फरेन्दा पुलिस को एक सफलता प्राप्त हुई। बताया जाता है कि थानाध्यक्ष फरेन्दा राघवेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 गोविन्द यादव व रि0का0 आकाश शर्मा पुलिस टीम द्वारा आज वृहस्पतिवार को मु0नं0 39/2026, धारा 115(2), 352, 351(3) बीएनएस से संबंधित वारंटी नसरुद्दीन पुत्र समसुद्दीन, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी वार्ड नं0-02, वाल्मीकि नगर, थाना बृजमनगंज, जनपद महराजगंज को गिरफ्तार किया गया।

पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन के सम्मान समारोह में पत्रकार हुए सम्मानित, सांसद व विधायक ने किया परिचय पत्र वितरित

नेबुआ, नौरंगिया,कुशीनगर।

जनपद कुशीनगर में पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन सम्मान और परिचय पत्र वितरण सामरोह का कार्यक्रम विकास खण्ड नेबुआ नौरंगिया के बृहस्पतिवार को ब्लॉक सभागार में सम्पन्न हुआ।

जिसमें इस संगठन के जिला पदाधिकारी और और तहसील खड्डा और तहसील कसानगंज के सभी पत्रकार पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुशीनगर सांसद विजय कुमार दुबे उपस्थित रहे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि खड्डा विधानसभा के विधायक विवेकानन्द पाण्डेय उपस्थित रहे। सांसद विजय दुबे ने सभी उपस्थित पत्रकार पदाधिकारी को परिचय पत्र और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किए। और मंच से संबोधन करके सभी पदाधिकारी को बधाई संदेश दिए कि समस्याओं को शासन-प्रशासन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। उन्होंने पत्रकारों से सत्य, निष्पक्षता और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया। मंच का संचालन पन्नेलाल ने किया। विकास खण्ड नेबुआ नौरंगिया के ब्लॉक प्रमुख शेषनाथ यादव कार्यक्रम में शरीक हुए।

जिलाध्यक्ष महेंद्र पाण्डेय के अगुवाई वाली कार्यक्रम में मंच से सभी पत्रकार पदाधिकारी ने मंच से संबोधन दिया और जिलाध्यक्ष ने अपने मुखर बिंदु से अपनी बातों को रखकर पत्रकारिता के बारे में अवगत कराए और समाज हित को लेकर और पत्रकार के संगठन को लेकर जोर दिया गया। यहां उपस्थित रहे पत्रकार पदाधिकारी में सुमंत दुबे प्रदेश उपाध्यक्ष, मण्डल महासचिव सुमन्त कुशवाहा, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष रोहित चौहान, संजय उपाध्यय, सच्चिदानंद कुशवाहा जिला महामंत्री, अरुण कुमार दुबे जिला मंत्री, अनुराग तिवारी जिला मंत्री, प्रभाती तिवारी जिला प्रवक्ता, विद्याधर तिवारी संरक्षक, अंकित कुशवाहा जिला मीडिया प्रभारी, महेश पासवान तहसील प्रभारी कसानगंज, तहसील अध्यक्ष ललित पांडेय, दिवाकर कुमार उपाध्यक्ष, फतेह आलम अंसारी मंत्री, रामचरण शुक्ल संगठन मंत्री, रवि प्रताप राव सूचना मंत्री, संदीप कुशवाहा, शैलेश यदुवंशी महामंत्री खड्डा, रामकोला ब्लाक अध्यक्ष योगेश गोविंद राव, जिला मंत्री गिरिजेश गोविंद राव , नंदलाल ,आदि पत्रकार पदाधिकारी उपस्थित रहे।

भटनी में ही बने वंदे भारत डिपो, रेल मंत्री से लगाई गुहार

भटनी देवरिया।

समाचार माध्यमों व स्थानीय सूत्रों से संज्ञान में आने के बाद कि भटनी में प्रस्तावित वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन डिपो को अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जा रहा है खबर पर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, भटनी ने रेल मंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। संगठन के प्रभारी सुमेश वर्मा ने रेल मंत्री को स्पीड पोस्ट के माध्यम से ज्ञापन भेजकर अनुरोध किया है कि डिपो की स्थापना का निर्णय भटनी के पक्ष में ही बरकरार रखा जाए और निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराया जाए। ज्ञापन में कहा गया है

उद्योग व्यापार मंडल ने ज्ञापन भेजकर कहा— परियोजना से क्षेत्र में रोजगार, व्यापार और विकास को मिलेगी नई रफ्तार

कि रेलवे प्रशासन डिपो निर्माण के लिए आवश्यक भूमि की प्रारंभिक जांच और पड़ताल पहले ही पूरी कर चुका है। ऐसे में परियोजना को अन्यत्र स्थानांतरित करना अब तक की गई तैयारियों और संसाधनों का अपव्यय होगा। व्यापार मंडल ने भटनी जंक्शन को पूर्वोत्तर रेलवे का ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण रेलवे केंद्र बताते हुए कहा कि यहां पर्याप्त रेलवे

उद्योग व्यापार मंडल प्रभारी सुमेश वर्मा

भूमि और आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे डिपो का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। संगठन का कहना है कि वंदे भारत डिपो बनने से भटनी सहित आसपास के क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी। व्यापार मंडल ने रेल मंत्री से जनभावनाओं का सम्मान करते हुए परियोजना को भटनी में ही स्थापित करने तथा निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने की मांग की है।

धान खरीद वर्ष 2026-27 की तैयारियां शुरू, अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) बने प्रभारी अधिकारी

कुशीनगर। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान खरीद कार्य को सुचारु, पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से संचालित करने के लिए जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) को जनपद का प्रभारी अधिकारी (धान खरीद) नामित किया है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार धान खरीद से संबंधित सभी तैयारियां समय पर पूरी की जाएं। साथ ही खरीद व्यवस्था की नियमित समीक्षा कर यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने अधिकारियों को धान खरीद केंद्रों पर किसानों की सुविधा, पारदर्शिता तथा आवश्यक व्यवस्थाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और किसी भी समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

नौवीं कक्षा में तीसरी भाषा: सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, कहा- छात्रों पर बढ़ेगा अनावश्यक तनाव

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सीबीएसई के तहत कक्षा 9 में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि नौवीं कक्षा में नई भाषा जोड़ने से छात्रों पर पढ़ाई का अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है और उनका तनाव बढ़ सकता है। अदालत ने सुझाव दिया कि तीसरी भाषा की पढ़ाई कक्षा 5 या 6 से शुरू की जानी चाहिए, ताकि बच्चे इसे आसानी से सीख सकें। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और आर. महादेवन की बेंच ने केंद्र सरकार से मौखिक रूप से कहा कि वे 9वीं क्लास में तीसरी भाषा शुरू न करें। जस्टिस नागरत्ना ने केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील से कहा, 'भारत सरकार, कृपया 9वीं क्लास के लेवल पर तीसरी भाषा न लाएं। इससे स्टूडेंट्स पर बेवजह तनाव बढ़ेगा। अगर आप कोई नई भाषा शुरू करना चाहते हैं, तो कृपया इसे 5वीं या छठी क्लास के लेवल पर करें, न कि 9वीं क्लास के लेवल पर। 9वीं क्लास तनावपूर्ण होती है, यह 8वीं क्लास से ही शुरू हो जाता है।' उन्होंने वकील से कोर्ट की यह बात सरकार तक पहुंचाने को कहा। ये टिप्पणियां तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान की गईं, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की सुविधा देने को कहा गया था। तमिलनाडु सरकार लगातार JNV खोलने का विरोध करती रही है, क्योंकि उसे इन स्कूलों में अपनाई जाने वाली 'तीन-भाषा नीति' वाले करिकुलम को लेकर चिंता है। पीठ सीधे तौर पर सीबीएसई की नई नीति के मुद्दे पर विचार नहीं कर रही थी, लेकिन अदालत ने स्कूलों में तीसरी भाषा शुरू करने के समय पर टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली एक अन्य सर्वोच्च न्यायालय की पीठ पहले से ही सीबीएसई की नई नीति को चुनौती देने से संबंधित मुद्दों की जांच कर रही है और हाल ही में अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान, तमिलनाडु सरकार के वकील ने बताया कि राज्य की आपत्ति तीन-भाषा नीति से संबंधित है। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने टिप्पणी की कि नीति में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, 'राज्य की भाषा पढ़ाई जानी चाहिए, अंग्रेजी पढ़ाई जानी चाहिए और कोई भी तीसरी भाषा। इसमें हिंदी का उल्लेख नहीं है।' उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता संगठन कुमारी महासभा की ओर से पेश अधिवक्ता जी प्रियदर्शनी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में साफ तौर पर उल्लेख है कि किसी भी राज्य पर कोई भाषा जबरन नहीं थोपी जानी चाहिए। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने तब राज्य से पूछा, 'आप हिंदी नहीं चाहते, लेकिन अगर संस्कृत है, तो क्या समस्या है?' राज्य के वकील ने जवाब दिया कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत तीसरी भाषा कक्षा 9 से ही अनिवार्य हो जाती है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा, 'नहीं, यह बहुत बुरा है।

क्लास 9 में बहुत तनाव होता है। आप क्लास 9 में नई भाषा क्यों शुरू करते हैं? इसे क्लास 6 में क्यों नहीं शुरू करते?' जस्टिस नागरत्ना ने अपने स्कूल के दिनों को भी याद किया और कहा कि क्लास 9 में यह चुनने का विकल्प होता था कि कौन सी भाषा पढ़नी है। उन्होंने कहा कि उनके स्कूल में छात्र मिडिल स्कूल के दौरान तीसरी भाषा सीखना शुरू कर देते थे। उन्होंने कहा, 'जिनकी दूसरी भाषा हिंदी थी, उनके लिए कन्नड़ होती थी और इसके उलट भी। संस्कृत भी थी, इसलिए आप तीसरी भाषा चुन सकते थे। जितनी जल्दी हो, उतना अच्छा है।' जस्टिस नागरत्ना ने तमिलनाडु सरकार से यह भी कहा कि वे केंद्र की योजनाओं को सिर्फ इसलिए खारिज न करें क्योंकि वे केंद्र से आई हैं। उन्होंने कहा, 'आपका अपना शिक्षा सिस्टम हो सकता है, लेकिन केंद्र सरकार के स्कूलों को न रोकें... आपको यह रवैया नहीं अपनाना चाहिए कि यह केंद्र सरकार की योजना है, तो हम इसे क्यों स्वीकार करें।' राज्य सरकार के वकील ने मामले पर सरकार से निर्देश लेने के लिए अदालत से कुछ समय मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु में नई सरकार बनी है, इसलिए यह देखना होगा कि नई सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है। मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के 2017 के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें राज्य के हर जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित करने का निर्देश दिया गया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की अनुमति न देना छात्रों के बेहतर शैक्षणिक संस्थान चुनने के अधिकार का उल्लंघन है और यह शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून, 2009 की भावना के खिलाफ है। राज्य सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2017 को हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। बाद में, 15 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में बदलाव करते हुए राज्य सरकार को हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया।

पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बड़ी खुशखबरी

जींद से दौड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन; कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ

चंडीगढ़ । भारतीय रेलवे के 170 से अधिक वर्षों के इतिहास में 17 जुलाई, 2026 का दिन स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है। इस दिन हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन का शुभारंभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसी को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। ट्वीट में पीएम ने कहा कि कल जींद से भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी, जो जींद और सोनीपत को जोड़ेगी। भारत उन चुनिंदा देशों में से एक बन जाएगा जिनके पास ऐसी ट्रेनें हैं। इससे यह पक्का करने में बहुत मदद मिलेगी कि भारत रेलवे सेक्टर में क्लीन टेक्नोलॉजी अपनाए। साथ ही कल जींद में दूसरे कामों का भी उद्घाटन होगा। इनमें सड़क और रेलवे प्रोजेक्ट शामिल हैं जो दिल्ली और अमृतसर, अंबाला और काला अंब, जींद और गोहाना वगैरह के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। भिवानी और नारनौल में मेडिकल कॉलेज भी देश को समर्पित किए जाएंगे।

कुरुक्षेत्र में एक सिख म्यूजियम की नींव रखी जाएगी। यह म्यूजियम सिख धर्म के शानदार इतिहास, आदरणीय सिख गुरुओं की महान शिक्षाओं और हमारे देश में सिख समुदाय के योगदान को दिखाएगा। मैं हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों के बीच रेलवे, हेल्थकेयर, कल्चर, कनेक्टिविटी, शिक्षा वगैरह से जुड़े अलग-अलग प्रोग्राम में हिस्सा लेने का इंतजार कर रहा हूं। इन कामों का लोगों की जिंदगी पर, खासकर हमारी युवा शक्ति की जिंदगी पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा।

नीट यूजी में 11.21 लाख अभ्यर्थी सफल, आर्यन गुप्ता और पंशुल बंसल ने किया टॉप

नई दिल्ली । नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने गुरुवार को नीट यूजी 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं, जिसमें कुल 11.21 लाख उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की है। इस वर्ष की परीक्षा में पंजाब और हरियाणा के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे देश में अपना परचम लहराया है।

पंजाब और हरियाणा के छात्र बने संयुक्त टॉपर

इस वर्ष की नीट परीक्षा में पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पंशुल बंसल ने 720 में से 715 अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल किया है। देशभर में केवल 19 उम्मीदवारों ने ही 700 से अधिक अंक प्राप्त करने का गौरव प्राप्त किया है। परिणामों के आंकड़ों के अनुसार, सफल होने वाले उम्मीदवारों में 58 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं, जिनका प्रदर्शन पुरुषों की तुलना में काफी बेहतर रहा है। परीक्षा में लगभग 20 लाख छात्र शामिल हुए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक 1.7 लाख उम्मीदवार सफल रहे हैं। एनटीए ने परिणाम जारी करने से पहले भौतिक विज्ञान के दो प्रश्नों में संशोधन किया था। मूल्यांकन नीति के तहत, एक प्रश्न को हटाने और दूसरे के दो सही उत्तर स्वीकार किए जाने के कारण सभी उम्मीदवारों को 8 बोनस अंक प्रदान किए गए हैं। सफल उम्मीदवार अब एमबीबीएस, बीडीएस, और आयुष पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे।

रायपुर में ई-20 पेट्रोल डालने से इंजन खराब

कंज्यूमर कोर्ट बोला- मारुति सुजुकी नई कार दे या 20 लाख लौटाए; देश का पहला मामला

रायपुर । देशभर में पेट्रोल में ई20 (20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित ईंधन) के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी बीच रायपुर में ई20 पेट्रोल से कार के इंजन के खराब होने का मामला सामने आया है। इससे जुड़े मामले में कंज्यूमर कोर्ट ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और उसके अधिकृत डीलर को जिम्मेदार ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि नई कार दी जाए या 20 लाख लौटाए जाएं। कोर्ट ने माना कि गाड़ी का इंजन ई-20 फ्यूल के हिसाब से नहीं था, फिर भी कार कस्टमर को बेची गई। कोर्ट ने कहा कि 45 दिनों के अंदर ग्राहक को उसी मॉडल की नई कार दी जाए, जो ई-20 फ्यूल के अनुकूल हो। अगर ऐसा नहीं किया तो कंपनी को वाहन की पूरी कीमत करीब 20.5 लाख रुपए और अन्य खर्च भी लौटाने होंगे। ई-20 से कार खराब होने पर कस्टमर को मुआवजा देने का यह देश का पहला मामला है। डॉ. प्रेमराज देवता ने बताया कि उन्होंने जून 2024 में मारुति सुजुकी की नेक्सा डीलरशिप से ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जेटा प्लस खरीदी थी। खरीदारी के समय डीलर ने बताया था कि कार दिसंबर 2023 में मैन्युफैक्चर हुई है, लेकिन बाद में आयोग के रिकॉर्ड से पता चला कि कार जनवरी 2023 में मैन्युफैक्चर हुई थी।

बागी नेताओं से राहुल गांधी नाराज- चन्नी को दिल्ली बुलाकर नहीं की मुलाकात

चंडीगढ़ । पंजाब कांग्रेस में बगावत की विस्तृत रिपोर्ट राहुल गांधी के टेबल पर पहुंच चुकी है। वे अब इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से चर्चा करेंगे। उसके बाद इस मसले पर हाईकमान की ओर से अंतिम फैसला लिया जाएगा। हालांकि नाराज नेताओं को हाईकमान ने दिल्ली बुला रखा था मगर राहुल गांधी ने बागी नेताओं के झंडाबरदार पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को मिलने का समय नहीं दिया। पार्टी सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी कार्यालय से चन्नी समेत अन्य नेताओं को संगठन सचिव केसी वेणुगोपाल से मिलने को कहा गया। उधर, केसी वेणुगोपाल को भी निर्देशित किया गया था कि वे वीरवार को नाराज नेताओं से बातचीत करेंगे और वीरवार को ही टिप्पणी समेत अपनी विस्तृत रिपोर्ट हाईकमान को सौंपेंगे। सूत्रों ने बताया कि देर शाम वेणुगोपाल ने अपनी रिपोर्ट राहुल गांधी कार्यालय को भेज दी है। वीरवार को बतौर सांसद एवं पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, सांसद एवं पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा, सांसद डॉ. अमर सिंह, विधायक परगट सिंह, विधायक सुखपाल सिंह खैरा समेत अन्य नाराज नेता दिल्ली पहुंचे हुए थे। दिल्ली में इन नेताओं की मुलाकात राष्ट्रीय महासचिव एवं कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला से भी हुई। उधर, केसी वेणुगोपाल ने सभी नेताओं से सामूहिक और वन-टू-वन मुलाकात कर इस पूरे विवाद में उनका पक्ष और राय जानी। वेणुगोपाल से बैठक के दौरान असंतुष्ट खेमे ने अपना दबाव बनाए रखा मगर नाराज नेताओं से संगठनात्मक बदलाव की जिद छोड़कर चुनाव से पहले एकजुटता बनाए रखने पर जोर देने को कहा गया। इस पर नाराज नेताओं ने केसी को बताया कि वे सूबे में चुनाव से पहले नेतृत्व परिवर्तन और सीएम फेस की मांग क्यों कर रहे हैं?

बघेल की भूमिका पर भी सवाल

पार्टी सूत्र बताते हैं कि केसी से बैठक के दौरान नाराज नेताओं ने पंजाब के प्रभारी भूपेश बघेल की भूमिका पर भी सवाल खड़ा किया। नाराज नेताओं का कहना था कि प्रभारी की ओर से उनकी बात सही ढंग से हाईकमान के समक्ष नहीं रखी गई। इसलिए वे हाईकमान से मिलना चाहते थे। बैठक में पंजाब संगठन की स्थिति, चुनावी तैयारियां और गुटबाजी पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रभारी भूपेश बघेल भी बुधवार को अपनी विस्तृत रिपोर्ट केसी वेणुगोपाल से मिलकर उन्हें सौंप चुके हैं। जिसमें उन्होंने बताया है कि 29 में से 25 जिला कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के समर्थन में हैं जबकि सात सांसदों में से चार सांसद वड़िंग के साथ हैं। रिपोर्ट में वड़िंग को अध्यक्ष बनाए रखने की सिफारिश की गई है। दूसरी ओर, दिल्ली बैठकों के समानांतर चन्नी समर्थकों ने सोशल मीडिया पर 'सारा पंजाब चन्नी दे नाल' अभियान तेज किया। यह अभियान हाईकमान पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेसियों की इस बगावत और दबाव की रणनीति के चलते हाईकमान असहज है।

ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका, टीएमसी सांसद कोयल मल्लिक ने दिया इस्तीफा

कोलकाता । बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार व सत्ता गंवाने के बाद तृणमूल कांग्रेस में जारी बगावत के बीच पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है। तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य अभिनेत्री कोयल मल्लिक (रुक्मिणी मल्लिक) ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कोयल ने उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया। सूत्रों के अनुसार, इस्तीफा सौंपने के बाद कोयल मल्लिक केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता भूपेंद्र यादव से मिलने दिल्ली में उनके आवास पर पहुंचीं। बंगाल में कोयल मल्लिक को लेकर दो महीने के भीतर राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यह चौथा इस्तीफा है। इससे पहले पिछले महीने सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बड़ाइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद ये तीनों पूर्व राज्यसभा सदस्य हाल में यहां भाजपा में शामिल हो गए। पार्टी में शामिल होने के कुछ ही घंटों के भीतर भाजपा ने तीनों को बंगाल में राज्यसभा की खाली हुई हुई तीन सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किया था। बंगाल विधानसभा में भाजपा के संख्या बल के हिसाब से राज्यसभा की खाली तीनों सीटों पर 24 जुलाई को होने वाले उपचुनाव में तीनों की जीत तय है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा: गुरुग्राम में पकड़े गए 13 बांग्लादेशी, कोई नहीं दिखा सका दस्तावेज; डिपोर्ट शुरू

गुरुग्राम । राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक बड़ी और प्रभावी कार्रवाई की है। पुलिस ने साइबर सिटी में अवैध रूप से रह रहे 13 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़कर उनके देश वापस भेजने (निर्वासन) की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गुरुवार को गुरुग्राम पुलिस की एक विशेष एस्कॉर्ट टीम इन सभी नागरिकों को लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना हो चुकी है।

क्राइम ब्रांच की टीम को मिली बड़ी कामयाबी

गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक, अपराध शाखा (क्राइम ब्रांच) सेक्टर-39 की टीम ने शहर में अवैध प्रवासियों की धरपकड़ के लिए एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया था। इसी अभियान के दौरान टीम ने खुफिया इनपुट और मुस्तैदी के आधार पर इन 13 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की। जांच के दौरान ये सभी भारत में वैध रूप से रहने के कोई भी पुख्ता दस्तावेज या प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके।

कड़े सुरक्षा पहरे में मालदा टाउन के लिए रवाना

भारत सरकार और सक्षम प्राधिकारी के आदेशों का अनुपालन करते हुए इन नागरिकों को डिपोर्ट करने की कागजी कार्रवाई पूरी की गई। गुरुग्राम पुलिस ने इनकी सुरक्षित रवानगी के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। सुरक्षा टीम: 01 निरीक्षक (इंस्पेक्टर) के नेतृत्व में 23 पुलिसकर्मियों की एक स्पेशल एस्कॉर्ट टीम तैनात की गई है। मालदा टाउन पहुंचने के बाद निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत इन्हें भारत-बांग्लादेश सीमा पर तैनात संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा, जहां से इन्हें इनके देश वापस भेज दिया जाएगा।

झुग्गियों से लेकर होटलों तक सघन चेकिंग अभियान

गुरुग्राम पुलिस ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। इसके लिए पुलिस की विभिन्न टीमें शहर के संवेदनशील इलाकों जैसे झुग्गी-झोपड़ियों, अवैध कॉलोनियों, किराए के मकानों, औद्योगिक क्षेत्रों और होटलों में रह रहे लोगों के दस्तावेजों और पहचान का सघन सत्यापन (वेरिफिकेशन) कर रही है। संदिग्ध पाए जाने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

गुरुग्राम पुलिस की जनता से अपील

पुलिस प्रशासन ने आम जनता और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस से इस अभियान में सहयोग की अपील की है। पुलिस ने नागरिकों के लिए कुछ जरूरी गाइडलाइंस जारी की हैं।

सत्यापन जरूरी: अपने घर में काम करने वाले किराएदारों, घरेलू सहायकों, कर्मचारियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से करवाएं।

संदिग्धों की सूचना दें: यदि आपके आसपास कोई भी संदिग्ध या अवैध रूप से रह रहा विदेशी नागरिक दिखाई दे, तो तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 112 या नजदीकी थाने को सूचित करें।

मानसून सत्र से पहले कांग्रेस का बड़ा प्लान, कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगी विपक्ष

नई दिल्ली । संसद के आगामी मानसून सत्र से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने संसदीय दल (सीपीपी) की नेता सोनिया गांधी के आवास पर गुरुवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक हुई। कांग्रेस ने बैठक में फैसला किया कि वह संसद के आगामी मानसून सत्र में केंद्र सरकार को शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी अनियमितता, पेपर लीक, राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी, एथनॉल से जुड़े विषय तथा कई अन्य मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगी।

पार्टी का यह भी कहना है कि वह इस सत्र में विदेश नीति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अल्पसंख्यकों के अधिकारों से जुड़े विषय प्रमुखता से उठाएगी।

पार्टी की संसदीय रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास '10, जनपथ' पर बृहस्पतिवार पूर्वाह्न एक बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव के. सी. वेणुगोपाल, राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे।

एथेनॉल मिश्रण को भी कांग्रेस बनाएगी मुद्दा

बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि ''चंदा चोरी-आस्था से धोखा, प्रश्नपत्र लीक और शिक्षा व्यवस्था का सुनियोजित पतन, संस्थानों पर कब्जा, राजनीतिक दलों को तोड़ना, अनेक घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप, कमरतोड़ महंगाई, विदेश नीति की विफलताएं और रणनीतिक भूलें, 3.5 करोड़ वाहन मालिकों पर एथेनॉल मिश्रण (ब्लेंडिंग) थोपना, बेलगाम वनों की कटाई तथा एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर लगातार हमले'' ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस मानसून सत्र में मोदी सरकार से जवाब मांगेगी।

20 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र

उन्होंने कहा कि कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में जनता के जीवन और भविष्य से जुड़े इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

सूत्रों के अनुसार, बैठक में संसद के भीतर विपक्षी दलों के साथ समन्वय, विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तथा सदन में पार्टी की प्राथमिकताओं पर भी विचार-विमर्श किया गया। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलने की संभावना है। सत्र शुरू होने से पहले विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' की भी सोमवार को बैठक प्रस्तावित है, जबकि सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है।

ट्रैक्टर-ट्रॉली तैयार हैं- वांगचुक के समर्थन में राकेश टिकैत का बड़ा एलान, सोनम की लगातार बिगड़ रही तबीयत

नई दिल्ली । कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का प्रदर्शन गुरुवार को 27वें दिन भी जारी रहा। प्रदर्शन के बीच 19 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की सेहत लगातार बिगड़ रही है। डॉक्टरों ने उन्हें 24 घंटे निगरानी में रखा है। इधर, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, सपा सांसद डिंपल यादव और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जंतर मंतर पहुंचे और सीजेपी के प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया। सोशल मीडिया पर फिल्मी सितारे भी सोनम के समर्थन में आ गए हैं। गुरुवार को जंतर-मंतर पहुंची डिंपल यादव ने कहा सोनम वांगचुक और अनशन पर बैठे छात्रों का संघर्ष देश के युवाओं के भविष्य के लिए है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव छात्रों और युवाओं के साथ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं की समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं है और लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने का प्रयास कर रही है।

टिकैत बोले- किसान अपने ट्रैक्टर के साथ तैयार

डिंपल ने देशभर के छात्रों, युवाओं और विपक्षी दलों से 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च में शामिल होने की अपील की। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की ट्रॉली और ट्रैक्टर तैयार है और 20 जुलाई को जंतर मंतर पर जनसैलाब आएगा। किसान और युवा मिलकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को मजबूत करेंगे।

बॉलीवुड से भी मिला साथ

बॉलीवुड के कई अभिनेताओं और अभिनेत्रियों ने सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई है। वहीं बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद और युवा भी सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट साझा कर रहे हैं। हजारों लोग वांगचुक के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए सरकार से बातचीत शुरू करने की मांग कर रहे हैं।

हेल्थ बुलेटिन

सोनम वांगचुक का वजन अब 56.90 किलोग्राम रह गया है। भूख हड़ताल शुरू होने के बाद से उनका वजन नौ किलो से ज्यादा कम हो चुका है। मेडिकल जांच में ब्लड प्रेशर 101/65 एमएमएचजी, ऑक्सीजन सैचुरेशन 98 प्रतिशत और रैंडम ब्लड शुगर 89 एमजी/डीएल दर्ज किया गया। डॉक्टर सतीश लांबा ने बताया कि वह पूरी तरह होश में हैं और मानसिक रूप से सतर्क हैं, लेकिन लगातार 19 दिनों से भोजन नहीं लेने के कारण उनका शरीर काफी कमजोर हो गया है। यही वजह है कि उनकी हर पल निगरानी की जा रही है।

हर वर्ग का मिल रहा साथ

सीजेपी के प्रदर्शन को लगातार समाज के हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। बृहस्पतिवार को जंतर मंतर पर युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं, दिव्यांगजनों, जेन जी के युवाओं और उनके माता पिता की भागीदारी देखने को मिली। प्रदर्शन में पहुंचे दिव्यांगजनों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने विश्वास जताया कि जनहित के मुद्दों पर एकजुट होकर आवाज उठाने से सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे।

दिल्ली को शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा: सीएम रेखा गुप्ता

नई दिल्ली । दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बृहस्पतिवार को कहा कि स्कूली बच्चों में ''राष्ट्र देवो भव'' की भावना पैदा किया जाना चाहिए ताकि वे इसे उच्च शिक्षा में आगे लेकर जा सकें और विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सकें।

सक्षम भारत

सक्षम भारत की बेवसाईड से जुड़ने के लिए दिए गए QR कोड को स्केन करे।